बजट फोकस: अर्थव्यवस्था, इक्विटी एवं रोजगार:

बजट में पहली बार

- व्यय एक लाख करोड़ रूपए से अधिक होगा।
- केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित सभी स्कीमों के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के लिए 100% प्रावधान।
- विकास संबंधी व्यय में 12% की वास्तविक वृद्धि।

महत्वपूर्ण आंकड़े:

- राजस्व प्राप्तियां: 91100 करोड़
- राजस्व व्यय: 62664 करोड़
- उपलब्ध राजस्व अधिशेष (पूंजीगत व्यय के लिए): 28436 करोड़
- पूंजीगत प्राप्तियां: 10329 करोड़
- पूंजीगत व्यय: 38764 करोड़
- जीडीपी में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 19.28% है।
- जीएसडीपी में प्रत्याशित वृद्धि: 11%

संघ राज्य क्षेत्र के संसाधन

- केन्द्रीय अनुदानों की पात्रता: 53%
- उधार: 11%
- केन्द्रीय करों का हिस्सा: 19%
- संघ राज्य क्षेत्र का अपना कर राजस्व: 13%
- संघ राज्य क्षेत्र का अपना स्वयं का गैर कर राजस्व : 4%

संघ राज्य क्षेत्र के व्यय का पैटर्न:

- संघ राज्य क्षेत्र का पूंजीगत/विकास संबंधी व्यय: 38%
- वेतन : 30%
- पैंशन: 7%
- ब्याज का भुगतान: 7%
- अन्य: 18%

केन्द्र सरकार की विकास संबंधी पहल:

- 30478 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता
- 279 करोड़ रूपए की आपदा मोचन निधि।
- 50000 रिक्त पदों को भरा जाना

राजस्व व्यय:

- प्रशासनिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 11627 करोड़ रुपए है, जिसमें से गृह विभाग पर 69.70% तक का व्यय किए जाने की आशा है।
- सामाजिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 20846 करोड़ रुपए है, जिसमें से शिक्षा विभाग पर 53.37% तक का व्यय किए जाने की आशा है।
- अवसंरचना क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 24523 करोड़ रुपए है, जिसमें से वित्त विभाग के माध्यम से 63.63% तक का व्यय किए जाने की आशा है।
- आर्थिक क्षेत्र का कुल राजस्व बजट 5541 करोड़ रुपए है, जिसमें से कृषि उत्पादन विभाग पर 25.01% तक का व्यय किए जाने की आशा है।

पूंजीगत व्यय:

- प्रशासनिक क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट 2074 करोड़ रुपए है, जिसमें से गृह विभाग पर 53.57% तक का व्यय किए जाने की आशा है।
- सामाजिक क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट 4969 करोड़ रुपए है, जिसमें से उच्च शिक्षा विभाग पर 27.41% तक का व्यय किए जाने की आशा है।
- अवसंरचना क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट 20404 करोड़ रुपए है।
- आर्थिक क्षेत्र का कुल पूंजीगत बजट 9952 करोड़ रुपए है, जिसमें से ग्रामीण विकास पर 53.09% तक का व्यय किए जाने की आशा है।

निवेश/विकास संबंधी पहल

विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण गतिविधियों की सूची

ग्रामीण विकास संबधी पहलें

- 350 लाख दिन का मजदूरी रोजगार सृजित किया जाएगा।
- 700000 घरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा।

- 90000 ग्रामीण परिसंपत्तियों (खेल के मैदान, नालियां, सुरक्षा दीवार, दाह संस्कार शैड इत्यादि) का निर्माण किया जाएगा।

- 79000 बेघर ग्रामीण परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत शामिल किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 55000 लाभग्राहियों को पक्के घर मुहैया कराए जाएंगे।

- 64899 बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 30075 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा 12310 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

- 200 नए पंचायत घरों का निर्माण किया जाएगा।
- 3650 संरपचों एवं 23160 पंचों के लिए एक्सपोजर दौरों का आयोजन किया जाएगा।

- 209500 महिलाओं को 20950 स्वयं सहायता समूहों के तहत शामिल किया जाएगा तथा इन्हें 31.42 करोड़ रुपए की रिवाल्विंग निधि मुहैया करायी जाएगी।
- 15900 स्वयं सहायता समूहों को 103.35 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि मुहैया कराई जाएगी।

- 1000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण।
- 200 ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
- 200 गोबरधन यूनिटों की स्थापना की जाएगी।

प्राथमिक क्षेत्र की प्राथमिकताएं

(कृषि/बागवानी)

- सीए भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 1.70 मीट्रिक टन तक किया जाएगा।
- अत्यधिक सघन वृक्षारोपण के तहत 355 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा
- क्षेत्र विस्तार के तहत 1500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
- 17 मौजूदा बाजारों के अलावा पांच सैटेलाइट मार्किटों को क्रियाशील बनाया जाएगा।
- कृषि यंत्रीकरण के तहत 5600 किसानों को कवर किया जाएगा और 1000 किसानों को उनकी फसल की सुरक्षित हैंडलिंग के लिए पैक हाउस उपलब्ध कराए जाएंगे।
- धान और मक्का की उत्पादकता को बढ़ाकर 1.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- 30000 किसानों को संकर सब्जी बीज और उच्च मूल्य वाली विदेशी सब्जी के बीज प्रदान करके लाभान्वित किया जाएगा
- 20000 किसानों को कृषि यंत्रीकरण के तहत कवर किया जाएगा जिससे खेती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी
- 1000 किसानों को अपनी आजीविका में सुधार करने के लिए 10000 बी-कॉलोनीज प्रदान की जाएगी।
- सुनिश्चित सिंचाई के साथ केसर की फसल की उत्पादकता 4 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर (2019-20) की तुलना में बढ़कर 4.5 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर हो जाएगी।
- 500 हेक्टेयर भूमि का उपयोग सुगंधित पौधों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा

- पर्यटन अवसंरचना के निर्माण और स्तरोन्नयन के लिए 560 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मुहैया करवाई जाएगी।
- प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं पर 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

- सभी उपभोक्तओं को बेहतर एव गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए विद्युत विकास विभाग को 4 उत्तरवर्ती कम्पनियों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम, विद्युत संवितरण कंपनी जम्मू, विद्युत संवितरण कंपनी कश्मीर तथा जम्मू एवं कश्मीर विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी के रूप में विभक्त किया जाना।
- बिजली की चोरी तथा इसकी बर्बादी को रोकने के लिए प्रवर्तन विंगों को सृजन
- शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाया जाना
- पुराने ट्रांसफार्मर के स्थान पर एनर्जी एफीशिएन्सी लेवल ।। ट्रांसफार्मर को लगाया जाना।
- विद्युत आपूर्ति को बेहतर करने के लिए कैपिसिटर बैंक लगाए जाना।.
- बकाया राजस्व की वसूली के लिए टैरिफ में संशोधन करना
- उपरोक्त सुधारों के लिए 607 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी गई है।

वन

- वर्ष 2020-21 के दौरान 14794 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 92 लाख पौधे उगाए जाने का प्रस्ताव है।
- 80.55 लाख रनिंग फीट में बाड़ लगाए जाने का प्रस्ताव है।
- 45 हेक्टेयर भूमि में 0.51 लाख औषधीय पौधे उगाए जाने हैं।

जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग

- "हर घर नल योजना" के तहत वर्ष 2022 तक सभी घरों को 100% पानी की आपूर्ति
- 180000 घरों में पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए 347 योजनाएं पूरी की जाएंगी
- 235000 वाटर सप्लाई नमूनों का परीक्षण किया गया जिससे 14 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए
- साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जल परीक्षण हेतु पंचायतों को फील्ड परीक्षण किट (एफटीके) प्रदान की

स्कूली शिक्षा

- शिक्षित और रोजगार के बीच के अंतर को कम करने के लिए तथा माध्यमिक स्तर पर छात्रों द्वारा स्कूल छोडने की दर कम करने के लिए 352 स्कूल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे 23,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे
- डिजीटल पहल के तहत स्कूली विद्यार्थियों को आधुनिक प्राद्योगिकियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए टैक्नोलोजी मिडिएटेड लर्निंग (टीएमएल) तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी/सीएएल) हेतु 175 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 224 सीएएल केन्द्रों की स्थापना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना.
- राज्य स्थानिक डेटा अवसंरचना केंद्र (जियो-पोर्टल) की स्थापना.
- औषधीय और सुगंधित पौधों के प्रदर्शन फार्मों की स्थापना।
- लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी (LCMS) की स्थापना।
- औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना।
- एमएनआरई, भारत सरकार की विकेंद्रीकृत सौर पीवी एप्लीकेशन स्कीम के तहत प्रत्येक जिले में 1000 एसएसएलएस की दर से 20000 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाया जाना

सामाजिक कल्याण

- पेंशन के 60000 नए मामलों को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के तहत कवर किया जाना।
- लाभग्राहियों को शत प्रतिशत छात्रवृत्ति कवरेज
- 32 कलस्टर जनजातीय आदर्श ग्रामों का विकास

अवसरंचना निर्माण

- सड़क क्षेत्र के लिए 310 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जिनसे 1.65 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित होंगे।
- 48 पुलों का निर्माण जिससे 1.60 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
- जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में मुगल रोड का सुधार.
- शहरी परिवहन प्रणाली के लिए पर्यावरण के अनुकूल 150 ई-बसें की खरीद।
- शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए जम्मू और श्रीनगर के लिए मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन का सृजन, ऐसे प्रत्येक निगम के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।
- जम्मू और कश्मीर आरटीसी में सुधार करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।
- पुरानी एवं असुरक्षित बसों को बदलने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 50 करोड की राशि रखी गई है।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान।

स्वास्थ्य-केन्द्रित स्थायी विकास लक्ष्य

- मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने, संचारी और गैर-संचारी रोगों को कम करने, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और लोगों को उनके घरों के नजदीक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिशन 2020 ।
- बारामूला, अनंतनाग, डोडा, राजौरी और कठुआ में चल रहे पांच नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य को पूरा करना
- हंदवाड़ा और उधमपुर में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यक सहायता का प्रावधान किया गया है।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति (HCIP) को लागू करना
- HCIP पहल के तहत जम्मू और श्रीनगर में Medi-Cities की स्थापना
- गरीब मरीजों के लिए सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु 86 जनऔषधि केंद्रों और 16 अमृत स्टोर्स की स्थापना
- प्रत्येक जिले में 20 डिजिटल डिस्पेंसरियां स्थापित करने के लिए 8 करोड़ रुपये रखे गए हैं

आईटी पहल के माध्यम से वित्तीय सुधार

- परियोजनाओं की रियल टाइम मानिटिरिंग तथा परियोजनाओं के जीपीएस निर्देशांक की पहचान के लिए JK PULSE नामक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की स्थापना।
- कोषागार के साथ आरबीआई के रियल टाइम इन्टीग्रेशन के लिए e-KUBER को लागू करना।
- बिलों की ऑनलाइन प्राप्तियों, व्यय की मानिटिरिंग के लिए कोषागारों में JK PAYSYS तथा एम्पलाय रिकार्ड कीपिंग एप्लीकेशन सिस्टम को लागू करना।
- सुदूर गाँवों को डिजिटल माध्यमों से दुनिया से जोड़ने के लिए डिजिटल ग्राम कार्यक्रम।
- BEAMS के माध्यम से Capex बजट के तहत परियोजनाओं का टैगिंग और कोडीफिकेशन।
- कार्यों की शत-प्रतिशत ई-टेडरिंग।
- परियोजनाओं का शत-प्रतिशत फिजिकल सत्यापन
- GeM पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।

कौशल विकास/खेलों को बढ़ावा देना

- 4000 छात्रों को उनके संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 1050 छात्रों को विरासत शिल्प पाठ्यक्रमों के तहत अपेक्षित कौशल प्रदान किया जाएगा।
- दो आदर्श आईटीआई की स्थापना की जाएगी।
- एक लाख खिलाड़ी विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेलों में भाग लेंगे।
- दस राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक पंचायत में खेल मैदानों की स्थापना करना।
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र

- आर्टिसन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1000 कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए 1.00 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट प्रावधान से ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- कारीगरों और खरीदारों के बीच प्रत्यक्ष बाजार संबंध मुहैया कराने के उद्देश्य से बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये के अनुमानित बजटीय प्रावधान से जम्मू एवं कश्मीर में तथा उसके बाहर 25 प्रदर्शनियों का आयोजन।
- नए विदेशी स्थलों की पहचान करने के लिए 25.00 करोड़ रुपये के अनुमानित बजटीय प्रावधान से एक्सपोज़र विजिट/मार्केट एक्सप्लोरेशन।
- 7.50 करोड़ रुपये (15000 प्रति प्रशिक्षु) के अनुमानित बजट प्रावधान से ।ICT/CDI और शिल्प प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण के माध्यम से 5000 कारीगरों का कौशल उन्नयन।
- 3.00 करोड़ रुपए (1 लाख रुपए प्रति सोसाइटी) के अनुमानित बजट प्रावधान से 300 सोसाइटियों के प्रस्तावित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हस्तकला समितियों के गठन हेतु प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित करने तथा प्रबंधकीय सब्सिडी प्रदान करने के लिए पास आउट प्रशिक्षुओं के लिए पोस्ट ट्रेनिंग पहल की शुरुआत करना।
- युवाओं के बीच उद्यमशीलता की भावना बढ़ाने के लिए प्रशिक्षुओं के लिए अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में 15.00 लाख रुपए के अनुमानित बजट प्रावधान से 100 प्रशिक्षुओं के लिए 6 जिलों में पायलट आधार पर 'Karkhadar Scheme' की शुरुआत ताकि उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।

- 5.00 करोड़ रुपये के अनुमानित बजटीय प्रावधान से 2000 एकल कारीगर इकाइयों को प्रदान की जाने वाली बैंक ब्याज राशि पर 10% की सब्सिडी।
- 50.00 लाख रुपए के अनुमानित बजट प्रावधान से 30 हथकरघा सहकारी समितियों के 325 बुनकरों को हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर 10% की विशेष छूट।
- प्रमोशन एवं मार्केटिंग पहल के रूप में 1.00 करोड़ रुपए के अनुमानित बजटीय प्रावधान से जागरूकता शिविरों / प्रदर्शनियों / फैशन शो /क्रेता-विक्रेता मुलाकात (बायर सैलर मीट) का आयोजन करना तथा विभिन्न एक्पो/ हैंडलूम इवेंट्स के लिए किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति।
- हथकरघा सहकारी समितियों के बुनकरों को नई करघों की मरम्मत, नवीनीकरण और खरीद के लिए 35.00 लाख रुपए के अनुमानित बजटीय प्रावधान से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- 6 लाख रुपये के अनुमानित बजटीय प्रावधान से 325 सदस्यों वाले 30 हथकरघा सहकारी समितियों को शेयर पूंजी ऋण सहायता प्रदान करना।
- खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से 25.00 करोड़ रुपए के अनुमानित बजटीय प्रावधान से जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (JKREGP) के तहत लगभग 7000 बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- ग्रामीण औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

अन्य पहलें

- मिशन यूथ के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान – युवाओं के उत्थान/रोजगार के लिए एक बड़ी पहल
- इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने तथा हाइब्रिड विग्योर को इन्फयूज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया / न्यूजीलैंड से 300 भेड़ तथा 120 मैरिनो रैम्स का आयात।
- कॉलेजों के निर्माण / उनके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
- गाँवों में बुनियादी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए "बैक टू विलेज" कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़पालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में स्वरोजगार के तहत 45000 नौकरियां सृजित की जाएंगी।
- सड़क के सरफेस में सुधार करने के लिए मैकडैमाइजेशन हेतु 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे लगभग 17 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- नई ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट में कचरे के निस्तारण और "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" को बढ़ावा देने सहित नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
- जम्मू-कश्मीर में निवेशकों के सम्मेलन के आयोजन हेतु 50 करोड़ प्रदान किए गए।
- विश्व प्रसिद्ध डल और वुलर झील के जीर्णोद्धार / संरक्षण के लिए 50 करोड़ दिए गए हैं।

- बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए की पूंजी प्रदान की गई है।
- **"Beat Plastic pollution"** अभियान के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- आबकारी विभाग द्वारा ऑनलाइन सेवाओं के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- सभी स्व-रोजगार योजनाओं को जेएंडके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नामक एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा ।
- जम्मू और श्रीनगर में समर्पित कला दीर्घाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक को 1 करोड़ रुपये की राशि दिए जाने का प्रस्ताव है
- संस्कृति और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।